साप्ताहिक
Live not just breaTHE

दि कार्मिक पोस्ट

MPHIN/2015/63220
MP/IDC1528/22-23

Global School Of Excellence, Obedullaganj

Email- thekaarmiicpost@gmail.com

वर्ष : 10, अंक : 50 (प्रति बुधवार), इन्दौर, 16 जुलाई 2025 से 22 जुलाई 2025 पेज : 8 कीमत : 3 रुपये

भोपाल की झीलों में माइक्रोप्लास्टिक की मौजूदगी चिंताजनक, एनजीटी ने मांगी रिपोर्ट

भोपाल भोपाल नगर निगम (बीएमसी) की ओर से पेश वकील ने एनजीटी को जानकारी दी है कि भोपाल में जल गुणवत्ता के संबंध में विशेषज्ञों द्वारा वैज्ञानिक अध्ययन किया गया है और रिपोर्ट दो सप्ताह के भीतर प्रस्तुत की जाएगी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की सेंट्रल बेंच इस मामले में अंतिम सुनवाई 8 अगस्त, 2025 को करेगी।

। विश्लेषण से पता चला है कि झीलों के पानी में बड़ी मात्रा में माइक्रोप्लास्टिक के कण मौजूद हैं। बड़ी झील में यह मात्रा 1,480 से 2,050 कण प्रति घन मीटर तक पाई गई, जबकि एक अन्य झील में यह मात्रा 2,160 से 2,710 कण प्रति घन मीटर तक थी। केरेवा डैम की जल गुणवत्ता की भी जांच की गई है, जिसमें पाया गया कि ट्रीटमेंट से पहले उसमें प्रति घन मीटर माइक्रोप्लास्टिक के 820 तक कण मौजूद थे, जो ट्रीटमेंट के बाद घटकर 450 रह गए। इसी प्रकार बिरला मंदिर के पास पानी में 450 कण, पिपलिया तालाब में 1765 से 2175 और देवधरम टेकरी में प्रति घन मीटर माइक्रोप्लास्टिक के 600 कण पाए गए। मेदिनीनगर के डिविजनल फारेस्ट ऑफिसर (डीएफओ) ने अपने हलफनामे में टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित उस खबर की पुष्टि की है, जिसमें बताया गया है कि झारखंड में पांच वन अधिकारियों पर पत्थर माफिया ने हमला किया। रिपोर्ट में इस घटना को एक पूर्व नियोजित आपराधिक साजिश बताया गया है, जिसे अवैध खनन में लिप्त लोगों ने कानूनन कार्रवाई रोकने और खनन विरोधी अभियान में शामिल अधिकारियों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से अंजाम दिया। ऐसे में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने 9 जुलाई, 2025 को पलामू के जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टर को दो सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। एनजीटी ने यह भी कहा है कि अधिकारियों को यह स्पष्ट करना होगा कि पर्यावरणीय हर्जाने की वसूली के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे। इसके साथ ही, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय दिया गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की पूर्वी पीठ ने कोलकाता महानगर विकास प्राधिकरण (केएमडीए) से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के निर्माण में आ रही अड़चनों पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। 9 जुलाई, 2025 को दिया यह आदेश रानाघाट नगरपालिका क्षेत्र के सरकारपाड़ा में प्रस्तावित 5.20 एमएलडी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) से जुड़ा है। इस प्लांट का निर्माण 0.78 एकड़ भूमि पर किया जाना है। कोलकाता महानगर विकास प्राधिकरण की ओर से पेश वकील ने अदालत से इस मामले को स्थगित करने का अनुरोध किया, ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि जिस 0.78 एकड़ जमीन पर एसटीपी बनना है, उसका कानूनी कब्जा राज्य सरकार ने लिया है या नहीं, और निर्माण में क्या अड़चनें हैं। 1 जुलाई, 2025 को केएमडीए की ओर से दायर हलफनामे में कहा गया है कि यह जमीन एक निजी मालिक की है, जिसे एसटीपी निर्माण के लिए चिह्नित किया गया है। हालांकि साथ ही यह भी कहा गया है कि राज्य प्रशासन द्वारा अब तक औपचारिक रूप से इस जमीन का कब्जा कोलकाता महानगर विकास प्राधिकरण को नहीं सौंपा गया है। यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि राज्य सरकार ने निजी मालिक से जमीन का कब्जा लिया है या नहीं। केएमडीए का कहना है कि जब तक जमीन का कब्जा उन्हें नहीं मिलता, तब तक एसटीपी निर्माण शुरू नहीं हो सकता। एनजीटी ने इस मामले में अगली सुनवाई से पहले विस्तृत जानकारी और जवाब दाखिल करने को कहा है। सोर्स - डाउन टू अर्थ

स्वच्छ ऊर्जा से चमकेगा भविष्य, 19.3 करोड़ लोग होंगे गरीबी मुक्त- रिपोर्ट

नई दिल्ली। एक नई रिपोर्ट से पता चला है कि अगर अक्षय ऊर्जा से जुड़े लक्ष्यों को सही नीतियों और निवेश के साथ जोड़ा जाए तो इससे न केवल वैश्विक अर्थव्यवस्था और पर्यावरण को फायदा होगा। बल्कि साथ ही करोड़ों लोगों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आएगा। अनुमान है कि इससे उन करोड़ों लोगों की जिंदगी बेहतर हो सकती है, जो आज भी गरीबी के भंवर जाल में फंसे हैं। इस रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी), डेनवर यूनिवर्सिटी और ऑक्टोपस एनर्जी ने मिलकर तैयार किया है। इसका मकसद यह समझना था कि अगर साफ ऊर्जा के लिए सही समय पर कदम उठाए जाएं, और सरकारें उसमें समझदारी से निवेश करें, तो उसका कितना फायदा होगा? रिपोर्ट के मुताबिक इस रणनीति को अपनाने से तीन बड़े फायदे मिल सकते हैं। इससे जहां बढ़ते उत्सर्जन में कमी आएगी। साथ ही आर्थिक विकास के साथ समाज के कमजोर तबके को भी फायदा मिलेगा। रिपोर्ट में जो निष्कर्ष साझा किए गए हैं, उनके मुताबिक इस बदलाव से ऊर्जा क्षेत्र में 20.4 ट्रिलियन डॉलर की बचत हो सकती है। साथ ही वैश्विक जीडीपी में 21 फीसदी की बढ़ोतरी और 2060 तक प्रति व्यक्ति औसत आय में 6,000 डॉलर का इजाफा हो सकता है, लेकिन अगर हम पुराने ढर्रे पर ही चलते रहें, तो ऐसा मुमकिन नहीं होगा। अपने इस अध्ययन में वैज्ञानिकों ने तीन अलग-अलग परिदृश्यों का तुलनात्मक विश्लेषण किया है। इसमें पहली स्थिति है कि जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहे। मतलब की दुनिया बदलावों को अपनाने की जगह पुराने ढर्रे पर ही चलती रहे। इस परिदृश्य मे यदि दुनिया 2060 तक अपनी ऊर्जा सम्बन्धी जरूरतों के 50 फीसदी के लिए कोयला, तेल जैसे पारंपरिक जीवाश्म ईंधनों पर निर्भर रहती है तो धरती बेहद गर्म हो जाएगी। अनुमान है कि इससे धरती का तापमान 2.6 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। इसका सीधा असर बिजली, पानी, खाना, शिक्षा, पोषण और स्वच्छता जैसे जरूरी विकास कार्यों पर पड़ेगा। आशंका है कि इसकी वजह से करोड़ों लोग गरीबी के गर्त में जा सकते हैं।

हिंदू कुश हिमालय में ग्लेशियर जनित बाढ़ में तेज वृद्धि -आईसीआईएमओडी

हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियर जनित बाढ़ों की संख्या में खतरनाक वृद्धि हो रही है। यह चेतावनी इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट (आईसीआईएमओडी) के वैज्ञानिकों ने दी है। ग्लोफ (ग्लेशियर लेक आउट बर्स्ट) तब होता है जब किसी पिघलते हुए ग्लेशियर से बनी झील से अचानक पानी निकल जाता है।

2000 के दशक में इस क्षेत्र में हर पांच से दस साल में एक बार ऐसी बाढ़ की संभावना होती थी। लेकिन केवल मई और जून 2025 के दो महीनों में ही आईसीआईएमओडी ने हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र में तीन ऐसी बाढ़ों को रिकॉर्ड किया है। ये घटनाएं नेपाल (लीमी), अफगानिस्तान (अंदराब घाटी), और पाकिस्तान (चित्राल, हंजा) में हुईं। आईसीआईएमओडी के डिजास्टर रिस्क रिडक्शन लीड सास्वत सान्याल ने कहा, इस प्रकार की घटनाओं की तीव्रता हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र में पहले कभी नहीं देखी गई है। हमें उन कारणों को गहराई से समझना होगा जो इन घटनाओं की श्रृंखला को उत्पन्न कर रहे हैं

हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र एशिया में 3,500 किलोमीटर तक फैला है और आठ देशों अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, भारत, म्यांमार, नेपाल और पाकिस्तान को शामिल करता है। यह क्षेत्र लगभग दो अरब लोगों की खाद्य, जल और ऊर्जा सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथ ही यह कई दुर्लभ और अपूरणीय प्रजातियों का घर है। ग्लेशियर जनित बाढ़ों का प्रमुख कारण तापमान में वृद्धि है। लगातार गर्मी ग्लेशियल झीलों के बनने और उनके फैलाव में अहम भूमिका निभाती है। वहीं, अत्यधिक तापमान वाले दिन बर्फीले भूस्खलन, ग्लेशियर के टूटने या स्थायी रूप से जमी हुई भूमि (पर्माफ्रॉस्ट) के पिघलने से ढलानों के खिसकने जैसी घटनाएं अचानक बाढ़ का कारण बन सकती हैं।

आईसीआईएमओडी ने एक नई प्रवृत्ति की भी पहचान की है। यह है हाल के ग्लोफ घटनाएं नई बनी हुई (सुप्राग्लेशियल) बर्फ से बाधित झीलों के टूटने से हुई हैं। इनमें इस सप्ताह नेपाल के रसुवा जिले में भोटेकोशी नदी में आई बाढ़ भी शामिल है। सुप्राग्लेशियल झीलें ग्लेशियर की सतह पर बनती हैं, विशेष रूप से मलबे से ढके क्षेत्रों में। ये शुरुआत में छोटे पिघले पानी के तालाब के रूप में बनती हैं और धीरे-धीरे फैलती जाती हैं। कभी-कभी ये आपस में मिलकर बड़ी झील बन जाती हैं, जिससे वे अत्यधिक गतिशील और अस्थिर हो जाती हैं। नेपाल में हाल ही में आई बाढ़ की वजह बनी झील दिसंबर 2024 में काफी छोटी थी, लेकिन कुछ महीनों में जून 2025 तक वह काफी बढ़ गई। पहले केवल 0.02 वर्ग किलोमीटर से बड़ी झीलों को जोखिमभरी माना जाता था। आईसीआईएमओडी के अनुसार, प्राथमिकता आमतौर पर नीचे की ओर प्रभाव डालने वाली और मोरेन-डैम्ड झीलों को दी जाती थी, क्योंकि वे विशेष रूप से अस्थिर मानी जाती हैं। वर्तमान में नेपाल में 25, चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में 21 और भारत में एक संभावित खतरनाक झील की पहचान की गई है। सुप्राग्लेशियल झीलों की पहचान करना कठिन है। लैंडसेट और सेंटीनेल -2 जैसे खुले उपग्रह डेटा की सीमित रेजोल्यूशन होती है और ये आमतौर पर केवल बड़े आकार की झीलों को ही पहचान पाते हैं, जिससे छोटी या अल्पकालिक झीलें छूट जाती हैं। उपग्रह इमेजरी की उच्च स्थानिक रेजोल्यूशन इन झीलों के पता लगाने में अहम है। वैज्ञानिकों ने मानचित्रण और निगरानी प्रयासों को बढ़ाने, संभावित खतरनाक झीलों की सूची को अपडेट करने, छोटी अवधि की बर्फ-डैम्ड झीलों का विश्लेषण करने और ग्लेशियरों के पीछे हटने और झील निर्माण की प्रक्रियाओं को शामिल कर ज्यादा गतिशील और सटीक खतरे के आकलन की सिफारिश की है।

भारतीय दूतावास स्तर पर स्थाई संपर्क तंत्र विकसित करने पर सहमति

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के तीन दिवसीय दुबई दौरे के दूसरे दिन की शुरुआत भारतीय कॉउन्सल जनरल श्री सतीश कुमार सिवन द्वारा आयोजित ब्रेकफास्ट ब्रीफिंग से हुई। बैठक में भारतीय दूतावास स्तर पर एक स्थाई संपर्क तंत्र विकासित किये जाने पर सहमति बनी जिससे मध्यप्रदेश और यूएई के बीच संस्थागत संवाद के निरंतरता बने रहे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश की छवि ब्रांड इंडिया के अंतर्गत वैश्विक स्तर पर सशक्त रूप से प्रस्तुत करने में भारतीय मिशन की निर्णायक भूमिका हो सकती है। ताज बिजनेस बे स्थित बॉम्बे ब्रैसरी में इस मुलाकात में मुख्यमंत्री डॉ. यादव को यूएई में भारत की विभिन्न गतिविधियों और संभावित सहयोग क्षेत्रों की जानकारी दी गई।

बैठक के दौरान जिन विषयों पर प्रमुखता से चर्चा हुई, उनमें मध्यप्रदेश प्रवासी व्यवसायियों को निवेश के लिए प्रेरित करने के विशेष प्रयास, दुबई-मध्यप्रदेश के बीच सांस्कृतिक एवं धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की संभावनाएं और दुबई में एमपी ड आयोजित करने के लिए भारतीय मिशन की भागीदारी जैसे अहम विषय शामिल रहे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने औद्योगिक, अधोसंरचना, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। बैठक में यह भी चर्चा हुई कि दुबई के प्रमुख औद्योगिक समूहों से मध्यप्रदेश उद्योग विभाग के सीधे संपर्क के लिए मिशन स्तर पर समन्वय किया जाएगा। साथ ही कृषि, टेक्सटाइल, ईवी, लॉजिस्टिक्स और पर्यटन जैसे प्राथमिक क्षेत्रों में कॉन्सुलेट की अगुवाई में सेक्टर-विशेष राउंडटेबल आयोजित करने का प्रस्ताव रखा गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इन सभी प्रस्तावों को सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ लिया। कॉउन्सल जनरल श्री सिवन ने जानकारी दी कि दुबई में कार्यरत मध्यप्रदेश मूल के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम से जुड़े व्यवसायियों की पहचान कर उन्हें प्रदेश सरकार की अनुकूल नीतियों से जोड़ा जा सकता है। तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में भी सहयोग की संभावनाएं रेखांकित की गईं, जिसमें विशेष रूप से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और सौर ऊर्जा से जुड़ी संस्थाएँ शामिल हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इन सभी प्रस्तावों को सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ लिया और कहा कि मध्यप्रदेश की छवि को ब्रांड इंडिया के अंतर्गत वैश्विक स्तर पर सशक्त रूप से प्रस्तुत करने में भारतीय मिशन की भूमिका निर्णायक हो सकती है।

ब्रीफिंग के दौरान अपर मुख्य सचिव नगरीय विकास एवं आवास श्री संजय दुबे, प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन श्री राघवेंद्र सिंह, प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति श्री शिवशेखर शुक्ला, सचिव एवं आयुक्त जनसंपर्क डॉ. सुदाम खाड़े सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत केंद्रीय मंत्री द्वारा रेवती रेंज में किया वृक्षारोपण

51 हजार से अधिक पौधों का रोपण

इंदौर, उद्यान प्रभारी राजेंद्र राठौर ने बताया कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव जी के एक पेड़ मां के नाम अभियान को आगे बढ़ाते हुए आज रेवती रेंज पहाड़ी पर एक बगिया मां के नाम अभियान के अंतर्गत माननीय भूपेंद्र यादव, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री, भारत सरकार, माननीय नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय तथा सामाजिक संगठनों एवं जनसहयोग के माध्यम से 51,000 से अधिक पौधों का रोपण किया गया। यह आयोजन पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता संवर्धन एवं हरित आवरण विस्तार की दिशा में एक प्रेरणास्पद पहल है। इस अवसर पर जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, सांसद शंकर लालवानी, विधायक रमेश मेंदोला, मधु वर्मा, गोलू शुक्ला, भाजपा नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा, जिला अध्यक्ष श्रवण चावड़ा, पूर्व विधायक जीतू जिराती, संजय शुक्ला, विशाल पटेल, हरिनारायण यादव,महापौर परिषद सदस्य राजेंद्र राठौर, निरंजन सिंह चौहान, बबलू शर्मा , निशांत खरे, चिंटू वर्मा, दीपक जैन क्षेत्रीय पार्षद सोनाली परमार एवं बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि गण एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी, छात्र-छात्राएं उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि इंदौर में स्वच्छता के साथ ही पर्यावरण संरक्षण एवं हरियाली के लिए जो काम किया है इस काम का संदेश प्रदेश ही नहीं देश-विदेश मैं भी जाएगा। मैं इंदौर शहर को बधाई देता हूं कि शहर के जागरूक नागरिकों ने एक पेड़ मां के अभियान के अंतर्गत इस स्थल पर इतने पेड़ों का संरक्षण करते हुए इन वृक्षों को जीवित रखा है। यह रेवती रेंज स्थल धरती का अमूल्य स्थल बन गया है, एक पेड़ मां के अभियान में 12 लाख से अधिक जो पौधे लगे हैं वह पौधे नहीं है धरती को एक अमूल्य उपहार दिया है। मालवा की धरती पावन और पवित्र होने के साथ ही हरियाली से आच्छादित है।? यहां पर प्रकृति का हरा भरा स्वरूप देखने को मिलता है, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में किए गए काम के लिए मैं नगरीय प्रशासन मंत्री और शहर की जनता के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत विगत वर्ष रेवती रेंज में 12 लाख 40 हजार से अधिक पौधों का रोपण किया गया था जो कि वर्तमान में भी जिंदा है यह अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि मां का हृदय इतना विशाल और पावन होता है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, मां शब्द छोटा है मगर इसके मायने कई गुना बड़े हैं, हमने मां के नाम से यहां पर जो पौधारोपण किए थे, वह वर्तमान में भी जीवित है, इस पावन काम में इंदौर के उद्यान प्रभारी राजेंद्र राठौर लगातार प्रयास रत रहे जिसका परिणाम है की आज यहां पर चारों ओर हरियाली लहरा रही है, यहां आकर बहुत ही सुकून मिलता है।उद्यान प्रभारी राजेंद्र राठौर ने बताया कि एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत इंदौर में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में पिछले वर्ष इसी अभियान के अंतर्गत रेवती रेंज पहाड़ी क्षेत्र में विश्व रिकॉर्ड स्तर पर 12.40 लाख पौधों का वृक्षारोपण किया गया था। इस ऐतिहासिक उपलब्धि को एक वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में इस वर्ष पुनः वृक्षारोपण का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के विभिन्न संगठनों के साथ ही छात्र-छात्राओं द्वारा भी पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर शहर भाजपा अध्यक्ष सुमित मिश्रा, माननीय मंत्री तुलसीराम सिलावट, सांसद शंकर लालवानी द्वारा भी संबोधित किया ओर आभार क्षेत्रीय पार्षद सोनाली परमार द्वारा व्यक्त किया गया।

देश में तेजी से लोकप्रिय हो रही फिजियोथेरेपी और आस्टोपैथ चिकित्सा पद्धति

इंदौर। फिजियोथेरेपी एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें मरीज को हॉस्पिटल में भर्ती होना जरूरी नहीं है। इसमें चीर - फाड़ भी नहीं होती और मेडिसिन भी जरूरी नहीं। केवल हाथ - पैरो के दवाब और आधुनिक मशीनों की मदद से चिकित्सा की जाती है। यह बात वरिष्ठ फिजियोथेरेपिस्ट डॉ. महेश साहू ने वर्कशॉप के समापन पर आयोजित प्रमाण पत्र वितरित कार्य क्रम में कहीं। डॉ. साहू ने कहा कि जिन मरीजो को घुटने का दर्द, जोड़ो का दर्द, स्लीप डिस्क, आर्थ-राइटिस, फ्रोजन शोल्डर की समस्याओ के कारण आपरेशन कराना पड़ता था, अब वे मरीज भी फिजियोथेरेपी चिकित्सा से ठीक हो रहे है। इस वजह से आपरेशन में भी कमी आई है। अब कोई भी मरीज बगैर डॉक्टर से संपर्क किये सीधे फिजियोथेरेपिस्ट से अपनी समस्याओ का निदान करा सकता है। फिजियोथेरेपी चिकित्सा पद्धति के साथ - साथ भारत में आस्टोपैथ चिकित्सा पद्धति भी तेजी से लोकप्रिय हो रही है। और लोगों का विश्वास भी बढ़ता जा रहा है। इस मौके पर फिजियो - थेरेपिस्ट डॉ. मनीष अरोड़ा, डॉ. पूजा गोयल, डॉ. कृष्णा जलोनिया, डॉ. मधुलिका सेठिया ने भी अपने विचार रखे। मीडिया प्रभारी प्रवीण जोशी ने बताया कि फिजियोथेरेपी और आस्टोपैथ की दो दिवसीय वर्कशाप में सभी 35 प्रतिभागियो ने अपने अनुभवों को शेयर किया। वर्कशॉप में इंदौर के अलवा देहरादून, भोपाल, उज्जैन, नीमच, प्रयागराज, लखनऊ आदि शहरो के 35 फिजियोथेरेपिस्ट शामिल हुए।

दुबई यात्रा का दूसरा दिन

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दुबई में JITO प्रतिनिधियों से किया संवाद

स्किलिंग, नवकरणीय ऊर्जा, टेक्नोलॉजी व संयुक्त निवेश फोरम की संभावनाओं पर चर्चा

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दुबई प्रवास के दूसरे दिन जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के प्रतिनिधियों के साथ निवेश और सहयोग को लेकर व्यापक चर्चा की। उन्होंने मध्यप्रदेश को वैश्विक निवेश, स्किलिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के सरकार के विजन को साझा किया और JITO समुदाय को प्रदेश की औद्योगिक प्रगति का भागीदार बनने के लिए आमंत्रित किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश आज लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी, स्थायित्व, दक्ष मानव संसाधन और अनुकूल औद्योगिक नीतियों के कारण निवेश के लिए देश का सर्वाधिक उपयुक्त राज्य बन चुका है। सरकार निवेशकों को न केवल आकर्षित कर रही है, बल्कि ज़मीन आवंटन से लेकर परियोजनाओं के क्रियान्वयन तक सक्रिय सहयोगी की भूमिका भी निभा रही है। बैठक के दौरान मध्यप्रदेश और JITO के बीच संभावित सहयोग के अनेक बिंदु पर चर्चा हुई जिनमें दुबई में एक वार्षिक 'MP-JITO निवेश फोरम की स्थापना करने पर भी विचार किया गया। इस फोरम के माध्यम से मध्यप्रदेश की लॉजिस्टिक्स, औद्योगिक पार्क, इलेक्ट्रिक वाहन, फूड प्रोसेसिंग और सेमीकंडक्टर जैसी प्रमुख परियोजनाओं को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस अवसर पर छ्ढ्ढञ्जह्र प्रतिनिधियों को आगामी निवेश फोरम के आयोजन का आमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि राज्य की नवीन लॉजिस्टिक्स नीति न केवल निर्यातकों को प्रोत्साहित करती है, बल्कि अधोसंरचना डेवलपर्स के लिए भी अनेक प्रावधान किए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने JITO से जुड़े टेक्सटाइल और फूड सेक्टर के कॉरपोरेट्स को उज्जैन, मंदसौर और बसई जैसे क्षेत्रों में ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स में भागीदारी के लिए आमंत्रित किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सुझाव दिया कि दुबई स्थित कौशल विकास संस्थान मध्यप्रदेश के ग्लोबल स्किल पार्क के साथ मिलकर संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करे, जिससे उद्योगों को कुशल मानव संसाधन मिल सके। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार ODOP यानि वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट के तहत दालें, तिलहन और प्रोसेस्ड फूड जैसे कृषि उत्पादों को वैश्विक बाज़ारों तक पहुँचाने के लिए JITO उद्यमियों के साथ समन्वय को प्राथमिकता दे रही है। बैठक के दौरान नवीकरणीय ऊर्जा और ड्रोन जैसे भविष्य के उद्योगों पर भी बातचीत हुई। मुख्यमंत्री ने छ्ढ्ढञ्जह्र से जुड़ी क्लीनटेक कंपनियों को प्रदेशमें पायलट प्रोजेक्ट्स शुरू करने के लिये आमंत्रित किया और बताया कि राज्य की नवकरणीय ऊर्जा नीति इन क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देती है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने यह भी उल्लेख किया कि हाल ही में संपन्न ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान मध्यप्रदेश को मिले ऐतिहासिक निवेश प्रस्तावों के बाद अब सरकार प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में निवेश केवल आर्थिक अवसर नहीं, बल्कि सामाजिक दायित्व भी है, जहां नए उद्यम, रोजगार और नवाचार को साकार रूप मिलेगा। बैठक में JITO के पदाधिकारी, टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ और प्रमुख उद्यमी उपस्थित रहे। उन्होंने मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया कि वे मध्यप्रदेश में स्किलिंग, टेक्नोलॉजी इनक्यूबेशन और सामाजिक परियोजनाओं में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। JITO प्रतिनिधियों ने प्रदेश के साथ दीर्घकालिक औद्योगिक संबंधों में रुचि जताई और एक विस्तृत निवेश संवाद आयोजित करने का प्रस्ताव भी मुख्यमंत्री को सौंपा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव की दुबई में शेख अहमद बिन सईद अल मकतूम से भेंट

मध्यप्रदेश बनेगा एविएशन और लॉजिस्टिक हब

भोपाल **(एजेंसी)** मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दुबई यात्रा के दौरान एमिरेट्स एयरलाइंस और दुबई सिविल एविएशन अथॉरिटी के चेयरमैन शेख अहमद बिन सईद अल मकतूम के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक मध्यप्रदेश और यूएई के बीच उड्डयन संबंधों को सुदृढ़ करने की दिशा में एक अहम पड़ाव साबित हुई।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि एयर एंबुलेंस फ्लाइट सेक्टर में अच्छी संभावना है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्ग दर्शन में मध्यप्रदेश एविएशन में जो काम कर रहा है उसमें भी दुबई सहयोग देने को तैयार है। बैठक में मुख्य रूप से इंदौर और भोपाल शहरों से दुबई के लिए सीधी विमान सेवाएं शुरू करने पर चर्चा हुई। मध्य भारत में एक क्षेत्रीय कार्गो हब स्थापित करने के प्रस्ताव पर भी सहमति बनी। एविएशन ट्रेनिंग और रूह्र (मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल) इन्फ्रास्ट्रक्चर में संयुक्त निवेश एवं प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना को लेकर भी सकारात्मक विचार-विमर्श हुआ। प्रदेश में इनबाउंड टूरिज्म को बढ़ावा देने और एमिरेट्स एविएशन अकादमी के कैंपस की स्थापना की संभावना पर भी गंभीर चर्चा की हुई। मध्यप्रदेश को भारत का एक प्रमुख एविएशन और लॉजिस्टिक्स हब बनाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो राज्य के आर्थिक और औद्योगिक विकास में नई उड़ान भरेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बैठक के बाद दुबई में मीडिया से संवाद करते हुए कहा कि आज सुबह से निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ अलग-अलग चर्चाओं का दौर शुरू हुआ है। सबसे पहले हमारे महावाणिज्यदूत और एंबेसी के लोगों के साथ विस्तार से चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि एयर एंबुलेंस फ्लाइट सेक्टर में अच्छी संभानाएँ है। मध्यप्रदेश एविएशन में जो काम कर रहा है दुबई उसमें सहयोग करने के लिए तैयार है। हमारी सरकार विदेश में कैसे आसानी से व्यापार करे, सरकार किन-किन क्षेत्रों में व्यापार कर सकती है, उस पर गहन विचार-विमर्श हुआ। मध्यप्रदेश में खदानें भी हैं, उद्योग भी हैं, फूड पार्क भी हैं। निवेशकों से अलग-अलग सेक्टर को लेकर चर्चा की।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक सोनल मेहता केलिए प्रतीक्षा ग्राफिक्स, 127 देवी अहिल्या मार्ग, इंदौर (म.प्र.) से मुद्रित एवं 209-बी शहनाई रेसीडेंसी-2 कनाड़िया रोड इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक: डॉ. सोनल मेहता फोन : 0731-2595008 Mail.sonal12mehta@yahoo.co.in 9755040008